Result Mitra Daily Magazine

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना

➢ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सोमवार (25 नवंबर) को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (One Nation One Subscription) नामक योजना को मंजूरी दी है।
- इस योजना के लिए 6000 करोड रुपए की बजटीय आवंटन की गई है।
- यह राशि अगले वर्ष यानि 2025, 2026 तथा 2027 के अंत तक के तीन कैलेंडर वर्षों के लिए उपलब्ध रहेगी।
- ONOS योजना जनवरी 2025 से छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों तथा भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI, Higher Education Institute)को बेहतर शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंचने में मदद करेगी।

➢ ONOS योजना क्या है ?

- भारत सरकार द्वारा देश के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं को एक विस्तृत एवं निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनवरी 2025 से उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक शोध लेखों तक राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए देश के शैक्षणिक संस्थानों में क्रांति लाना है।

- इस योजना का लक्ष्य देश के सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के लिए जर्नल एक्सेस को समेकित करना है।
- यह योजना केंद्र और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों को एक मंच पर हजारों पत्रिकाओं तक पहुंचने में सक्षम करेगा।
- ONOS भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को एल्सेवियर साइंस डायरेक्ट, लैंसेट, स्प्रिंगर नेचर, विली ब्लैकवेल पब्लिशिंग, टेलर एंड फ्रांसिस, स्टेज पब्लिशिंग, अमेरिकन केमिकल सोसायटी और अमेरिका मैथमेटिकल सोसायटी सहित 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 13,000 से अधिक पत्रिकाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा।
- सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को इन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक पहुंचने के लिए केवल ONOS के तहत पंजीकरण करना होगा।
- ONOS के तहत पंजीकरण के लिए INFLIBNET नामक कार्यान्वयन एजेंसी को नामित किया गया है।
- INFLIBNET (इन्फ्लिबनेट) भारतीय शिक्षा मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर–विश्वविद्यालय केंद्र है, जो देश में पुस्तकालयों एवं सूचना संसाधनों को बढ़ावा देता है।
- INFLIBNET की स्थापना मार्च 1991 में एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में की गई थी।
- भारत की उच्च शैक्षणिक संस्थानें (HEIs)वर्तमान में पत्रिकाओं तक कैसे पहुंचते हैं ?
- वर्तमान में भारत की उच्च शैक्षणिक संस्थानें 10 विभिन्न पुस्तकालय संघों जो विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में है, के माध्यम से पत्रिकाओं तक पहुंचते हैं।
- उदाहरण के लिए गुजरात के गांधीनगर स्थित INFLIBNET केंद्र जो भारत की यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्सियम की देखरेख करता है, चयनित इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं तक उच्च शैक्षणिक संस्थानों की पहुंच बनाता है।
- इसके अलावा HEIs व्यक्तिगत रूप से भी कई पत्रिकाओं के सदस्यता लेता है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत के HEIs उपरोक्त पुस्तकालय संघ और व्यक्तिगत सदस्यता के माध्यम से लगभग 8100 पत्रिकाओं तक अपनी पहुंच बनाए हुए हैं।

➢ भारत में ONOS की क्या आवश्यकता है ?

- ONOS भारत के लगभग 6300 सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान निकायों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (INI, Institute of National Importance)के लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं तक सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं की पहुंच को बनाएगा।

- ONOS विभिन्न पुस्तकालय संघों और व्यक्तिगत उच्च शिक्षा संस्थानों में जर्नल सदस्यता के दोहराव से बचाकर अतिरिक्त व्यय को कम करने में मदद करेगा।
- ONOS केंद्र और राज्य सरकार की सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रकाशकों के साथ एकल सदस्यता हासिल करने के लिए बेहतर सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करेगा।
- ONOS से केंद्र इस बात की जानकारी हासिल करेगा कि विभिन्न सरकारी उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा पत्रिकाओं को किस हद तक एक्सेस और डाउनलोड किया जाता है।

➢ ONOS की संकल्पना :

- ONOS की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP, National Education Policy) से शुरू हुई, जिसमें शिक्षा और राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान पर जोर दिया गया है।
- NEP–2020 के तहत भारत के उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने सहित इसे वित्त पोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF, National Research Foundation) की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
- इस सिफारिश के तहत वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी बनाकर ONOS पहल के लिए जर्नल प्रकाशकों से मजबूत बातचीत करने के लिए एक लागत वार्ता पैनल का गठन किया गया था।
- वर्ष 2023 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF, Anusandhan Nati Research Foundation) की स्थापना के साथ ही ONOS की संकल्पना की गई।
- ONOS के उपयोग की निगरानी और समय-समय पर इसके मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के पास है।

➢ ONOS लागू करने वाले अन्य देश :

- नेचर जनरल में छपी एक लेख के अनुसार, भारत द्वारा शुरू की गई ONOS योजना दुनिया में नई नहीं है।
- भारत से पहले जर्मनी और उरुग्वे जैसे देशों ने शोध सामग्री की राष्ट्रीय पहुंच के लिए इस तरह की योजना लागू की थी।

➢ ONOS लागू होने के बाद आगे क्या होगा ?

- देश में ONOS की मंजूरी के साथ ही केंद्र सरकार का अगला कदम जर्नल प्रकाशकों के साथ आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (APC) पर बातचीत करना होगा।
- आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (APC) को प्रकाशन शुल्क के रूप में जाना जाता है, वे शुल्क होते हैं जिन्हें लेखकों को कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए भुगतान करना होता है।
- ओपन एक्सेस जर्नल आमतौर पर लेख प्रसंस्करण के लिए एक विशिष्ट शुल्क लेते हैं जिसे APC के रूप में जाना जाता है।
- सरकारी अनुमानों के अनुसार भारत में लेखकों ने वर्ष 2021 में APC के रूप में जर्नल प्रकाशकों को लगभग 380 करोड रुपए का भुगतान किया।
- केंद्र सरकार के अनुसार APC के लिए पत्रिकाओं के साथ बातचीत करने के लिए मंत्रालयों के विशेषज्ञों के विषय–विशिष्ट समूह बनाए जाएंगे।